gmßVm{hH$

सृष्टी ॲग्रो

● वर्ष : 1 ● अंक : 1 ● मुंबई, 01 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी 2013 ● पाने : 8 ● किंमत : 2/- रुपये

महंगाई से निपटने में लगे है कृषि वैज्ञानिक, सब्जी की आधुनिक खेती सिख रहे है किसान

नयी दिल्ली, २९ अप्रैल (एजेंसी) : बढती महंगाई खासकर सब्जियों की ऊंची कीमत से निपटने के उद्देश्य से कृषि वैज्ञानिक बारहमासी उगने वाली सब्जियों की खेती के गुर किसानों को सिखा रहे हैं।

हरियाणा के करनाल जिले के घरौंडा कस्बे में इस्त्राइल के सहयोग से बना सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के कृषि वैज्ञानिक उत्पादकता बढाने के लिये किसानों को हर मौसम में उगने वाले टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन, मिर्च जैसी सब्जियों के बीज उपलब्ध कराने के साथ पाली हाउस में खेती करने तथा उपज बढाने के आधुनिक तौर-तरीकों से परिचित करा रहा है।

बारहमासी उत्पादन संभव होने से बाजार में लगभग पूरे साल इसकी उपलब्धता बनी रहेगी जिससे कीमत नियंत्रित रखी जा सकती है।

हरियाणा के बागवानी विभाग के अतिरिक्त निदेशक डाक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने १भाषा से कहा, "राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत चलायी जा रही परियोजना का मकसद अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है...यहां हम किसानों को खेती के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से रूबरू कराते है। वे इस प्रौद्योगिकी को समझते हैं और उसका उपयोग कर अपने खेतों में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करते हैं। "

दरअसल फल एवं सब्जी बाजार में एक समय में आती है। कुछ फल एवं सब्जी को छोड दें तो इसे ३ से ४ सप्ताह से ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता। ऐसे में सीजन समाप्त होने

के बाद संबंधित फल-सब्जी की कीमत बढती है। इसी स्थिति से निपटने के लिये इस्त्राइली कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से यह केंद्र काम कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में महंगाई खासकर फल एवं सब्जी की कीमत काफी बढी है। हालांकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष मार्च महीने में ६.८९ प्रतिशत रही जो नवंबर २०११ तक १० प्रतिशत के आसपास बनी हुई थी। बहरहाल, खाद्य वस्तुओं की कीमत अभी भी उच्चंची बनी हुई है।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रमुख तथा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के सलाहकार डाक्टर एस के अरोडा ने कहा, इस संरक्षित ढांचा :पाली हाउस: में किसान कोई भी सब्जी किसी भी मौसम में उगा सकेंगे जबकि खुले खेत में यह संभव नहीं है। इन स्थानों पर उगायी गयी सब्जियों के लिये कीटनाशकों की जरूरत नहीं पडती।

सैनी ने कहा, दिल्ली से करीब होने के कारण हरियाणा इस प्रकार के उत्पाद के लिये प्रमुख बाजार है और किसान बिना मैसम वाली स्वास्थ्यवर्द्धक सब्जी का उत्पादन कर उच्चंची कीमत प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस तकनीक के जरिये उपजायी गयी सब्जियों की कीमत परंपरागत तरीके से उगायी सब्जियों की कीमत से काफी अधिक है। इससे किसान जरूर लाभान्वित होंगे लेकिन महंगाई से परेशान आम उपभोक्ताओं को इस केंद्र का फिलहाल कोई लाभ नहीं दिखता।

इस बारे में सैनी ने कहा, निश्चित रूप से अभी कीमत अधिक है लेकिन जैसे-जैसे तकनीक का प्रचलन और मांग बढेगी, कीमत कम होगी।

सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के मुख्य सलाहकार डाक्टर एस के अरोडा ने कहा, इस संरक्षित ढांचा : पाली हाउस: में किसान कोई भी सब्जी किसी भी मौसम में उगा सकेंगे जबकि खुले खेत में यह संभव नहीं है। इन स्थानों पर उगायी गयी सब्जियों के लिये कीटनाशकों की जरूरत नहीं पडती।

सैनी ने कहा, दिल्ली से करीब होने के कारण हरियाणा इस प्रकार के उत्पाद के लिये प्रमुख बाजार है और किसान बिना मैसम वाली स्वास्थ्यवर्द्धक सब्जी का उत्पादन कर उच्चंची कीमत प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि इस तकनीक के जरिये उपजायी गयी सब्जियों की कीमत परंपरागत तरीके से उगायी सब्जियों की कीमत से काफी अधिक है। इससे किसान जरूर लाभान्वित होंगे लेकिन महंगाई से परेशान आम उपभोक्ताओं को इस केंद्र का फिलहाल कोई लाभ नहीं दिखता।

इस बारे में सैनी ने कहा, निश्चित रूप से अभी कीमत अधिक है लेकिन जैसे-जैसे तकनीक का प्रचलन और मांग बढेगी, कीमत कम होगी।

दिल्ली में मोदी की दावेदारी

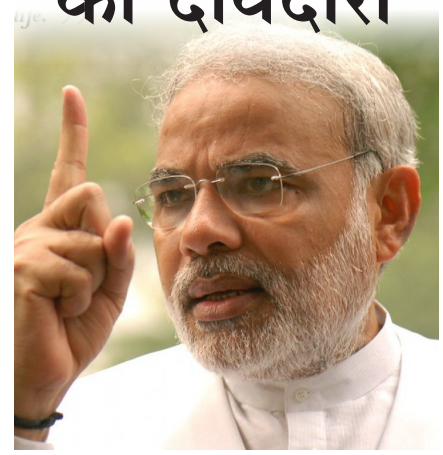

गुजरात में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम से मोदी का भविष्य तय होगा। प्रधानमंत्री पद के लिए उत्तर प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम भी शामिल है। माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाकर सेक्युलर दलों का समर्थन प्राप्त कर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। (पान ७ पर)

किसानों की आत्महत्या में महाराष्ट्र की स्थिति बदतर

महाराष्ट्र में किसानों के आत्महत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल २०११ में ३,३३७ किसानों ने आत्महत्या की है। यह पिछले साल २०१० की अपेक्षा और भी बदतर है, जहां पिछले साल ३,१४१ किसानों ने खुदकुशी की जो इस साल बढकर ३,३३७ जा पहुंची है।

ताजा मामले में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पिछले ७२ घंटे के अंदर छह और किसानों ने आत्महत्या कर ली। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा रविवार को जारी आंकडों के अनुसार इस वर्ष अब तक ४२२ किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। मानसून में देरी के कारण जिन किसानों ने बुवाई कर दी है उनमें घबराहट फैल गई है।

कानपुर में 'जीरो बजट' खेती

जीरो बजट खेती यानी १हींग लगे न फिटकरी रंग भी आए चोखा । ऐसी खेती जिसमें सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। कानपुर और उसके आसपास के करीब १०० एकड क्षेत्र में इस तरह की खेती जोर पकडने लगी है। किसानों में इसे काफी पसंद किया जा रहा है।

इस तरह की खेती में कीटनाशक, रासायनिक खाद और हाईब्रिड बीज किसी भी आधुनिक उपाय का इस्तेमाल नहीं होता है। यह खेती पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इस तकनीक में किसान भरपूर फसल उगाकर लाभ कमा रहे हैं, इसीलिए इसे जीरो बजट खेती का नाम दिया गया है। (पान ७ पर)

घर बैठे मिलेंगे आधुनिक खेती के गुर

सोलन : हिमाचल में अब घर बैठे बागबानी व कृषि सबंधी तकनीकी जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि डा. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौणी के वैज्ञानिक ग्रामीणों को घर-द्वार पर इसकी जानकारी देंगे। यूनिवर्सिटी का विस्तार शिक्षा निदेशालय प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान व बागबानों के लिए शिविरों का आयोजन करेगा। विवि के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. जीके शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर फसल गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, इसमें आधुनिक बागबानी व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से ग्रामीण विकास पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने के लिए यूनिवर्सिटी ने विशेषज्ञों की आठ टीमों का गठन किया है, जो प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग विषयों के बारे में किसानों को जागरूक करेंगे। इसमें यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी भाग लेंगे, इसमें करीब ३० वैज्ञानिक होंगे। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है, इससे किसानों को क्या-क्या लाभ होंगे। बगीचों का रखरखाव कैसे करना है, आदि के बारे में तमाम जानकारी किसानों को दी जाएगी। डा. शर्मा ने बताया कि इसी कडी में १८ व १९ फरवरी को मंडी जिला के करसोग में किसानों के लिए शिविर व फसल गोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। इस दौरान गोष्ठी के दौरान किन्नौर, कुल्लू, कोटखाई, मशोबरा व नौणी के कृषि वैज्ञानिक शामिल रहे। (पान ७ पर)

ग्रीन हाउस लगा कर आधुनिक खेती करने का बढा प्रचलन

बिलासपुर, २६ जून (हप्र)। जिला में ग्रीन हाउस लगा कर आधुनिक ढंग से खेती करने का प्रचलन बढने लगा है। गरीब किसान भी बांस के ग्रीन हाउस लगा कर अपनी आर्थिकी मजबूत कर रहे हैं। जिला बिलासपुर में वर्ष २०११-१२ में १२५ बांस के ग्रीन हाउस लगाए जा चुके हैं। सरकार बांस के ग्रीन हाउस लगाने पर किसानों को नब्बे प्रतिशत अनुदान दे रही है। ये उदगर आज यहां बचत भवन में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में कृषि उपनिदेशक डा. जी लखनपाल ने व्यक्त किए। यह कार्यक्रम एडीएम दर्शन कालिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें बताया गया कि जिला में गत मार्च तक ९७४ ग्रीन हाउसों का निर्माण किया जा चुका है।

प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बताया गया कि इस वर्ष ०.५३२० हेक्टेयर क्षेत्र में बांस के व ०.२२७१ हेक्टेयर क्षेत्र में जीआई ग्रीन हाउस स्थापित किए गए जिनको १६ लाख रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। महिलाओं का कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान रहता है। यह बताते हुए लखनपाल ने कहा कि जिला में महिलाओं के अब तक ४५ स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन समूहों में महिलाओं को कृषि की आधुनिक तकनीकी संबंधी प्रशिक्षण शिविर, प्रदर्शन व भ्रमण कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता तथा गुणवत्ता बढाने के लिए जैविक कृषि की ओर किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु दो किलो केंचुए के किट मुफ्त दिए जा रहे हैं। जो भी बीज दिया जाता है वह सौ प्रतिशत उपचारित होता है।

किसान करेंगे आधुनिक तकनीक से खेती

ग्रेटर नोएडा : किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक से रुबरू कराने के लिए उद्यान विभाग किसानों के एक दल को विभिन्न स्थानों का दौरा कराएगा। दौरे में दिल्ली स्थित भारतीय कृषि शोध संस्थान भी शामिल है। दल में जिले के पचास किसान होंगे। ब्लॉक स्तर पर किसानों के चयन की कार्रवाई शुरू हो गई है। दौरा फरवरी के अंत में होगा।

भारत कृषि प्रधान देश है। खेती में दिन प्रतिदिन आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढता जा रहा है। जिससे कम लागत में पैदावार ज्यादा होती है। साथ ही किसानों को मेहनत भी कम करनी पडती है। जानकारी न होने से किसान खेती की सदियों पुरानी पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। उद्यान विभाग किसानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी देगा। जिला उद्यान अधिकारी एनके सहानिया ने बताया कि शासन द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जाएगी। अलग-अलग ब्लॉक से पचास किसानों का चयन किया जाएगा। ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्वयं खेती कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक से खेती की पैदावार बढाना चाहते हैं। किसानों को चार स्थान मोदीपुरम विश्वविद्यालय, सहारनपुर रिसर्च सेंटर, करनाल व पूसा का दौरा कराया जाएगा। आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए शुरू होने वाला दौरा एक सप्ताह का होगा। उन्होंने बताया कि दौरे के लिए किसानों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दौरे में प्रमुख रुप से सब्जी, फूल व फल की खेती की जानकारी दी जाएगी।

राजनीति का नाजुक दौर

भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही हैं। एक ओर महंगाई बढती जा रही है वहीं दूसरी ओर रुपये का अवमूल्यन रुक नहीं पा रहा है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए राजनीतिक एकजुटता जरूरी है, लेकिन ऐसा करने की बजाय राजनीतिक तिकडमों में समय गंवाया जा रहा है। आज यह कहना बहुत मुश्किल है कि कल कौन सा दल किसका समर्थन करेगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति पद के दावेदारों में उनका नाम नहीं था। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से वार्ता के बाद ही उनका नाम आगे बढाया था। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें अपने किसी अन्य उम्मीदवार के जीतने का भरोसा नहीं था। कह सकते हैं कि सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी को मजबूरी में उम्मीदवार बनाया। अब मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद प्रणब मुखर्जी के निर्णयों की समीक्षा शुरू कर दी है और संकेत हैं कि बहुत से निर्णय पलटे जा सकते हैं। कभी क्षेत्रीय दलों का गठबंधन निर्णायक हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वे अलग-अलग दिशाओं में भटक रहे हैं। अभी से चर्चा शुरू हो गई है कि २०१४ में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेसी खेमे में राहुल गांधी की चर्चा है तो भाजपा नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिख रही है।

यद्यपि भाजपा ने मोदी के नाम की घोषणा खुलकर नहीं की है, लेकिन वह इस पद के लिए जनता की पसंद हैं।

गुजरात, कर्नाटक की हालत सोचनीय

रिपोर्ट में कहा गया है कि २००४-२०११ के बीच की अवधि में किसानों के बीच आत्महत्या की प्रवृति में कमी आई है। साल २००४ में हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा १८,२४१ किसानों ने आत्महत्या की थी। यूपीए सरकार के २००४ में देश की बागडोर संभालने के बाद कुल १.१८ लाख किसानों ने अब तक आत्महत्या की है। गुजरात, कर्नाटक और उत्तरप्रदेश कुछ ऐसे राज्यों के नाम हैं जहां वर्ष (२००४-२०११) के दौरान किसानों के बीच आत्महत्या करने की प्रवृति बढी है।

दिखावा साबित हुए विशेष पैकेज

खेती की समस्या से जूझते इन राज्यों के अलावा सबसे चौकाने वाले तथ्य तो असम जैसे पूर्वोतर राज्य से सामने आए हैं जहां २०१० में २६९ किसानों ने आत्महत्या की थी जो २०११ में बढकर ३१२ तक पहुंच गई है। साथ ही इन आंकडों से इस बात का पता चलता है कि बुंदेलखंड और विदर्भ जैसे सूखा प्रभावित राज्यों को दिए जाने वाले विशेष पैकेज महज मात्र एक दिखावा साबित हो रही है।

पंजाब में होगी आधुनिक तरिके से खेती

होशियारपुर। हालही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंधकीय बोर्ड के सदस्य व प्रसिद्ध बागवान कुलवंत सिंह इटली के बलोनिया में हुई अंतराष्ट्रीय कृषि एवं बागबानी उपकरण प्रदर्शनीमें हिस्सा लेकर लौटे हैं। वहापर बागवानी को लेकर काफी रिसर्च किया जा रहा है। जिसे देखते हुए कुछ अहम् कदम यहाँ पर भी उठाने की संभावना है।

कुलवंत सिंह ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश का ११ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वित्त कमिश्नर रिसर्च डेवलेपमेंट गुरिंदर सिंह संधू की अध्यक्षता में बलोनिया में आयोजित इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने गया था। जहां हम लोगों नेबागवानी की कई तरह की नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की है। पंजाब कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी कृषि के आधुनिकीकरण में बहुत पिछड रहा है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार कृषि व बागवानी के आधुनिकीकरण को लेकर काफी संजीदगी से सोच रही है।

कुलवंत सिंह ने बताया कि इस तरह का सेंटर पंजाब में भी शुरू करने के लिए वह मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से भी बात करेंगे। जिसमे विदेश में बन रही तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में कृषि क्षेत्र में उपयोगी अति आधुनिक व सरल ढंग से चलाने योग्य कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। ऐसा स्प्रे है जो कीटनाशक हरेक पत्ते तक पहुचता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कटाई, प्रूनिंग व बिजाई की अति आधुनिक मशीनें भी प्रदर्शनी में दिखाई गई। इन सब मशीनों के प्रयोग से कृषिव बागवानी के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। अति आधुनिक मशीनों की हमारे किसानों को भी बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं किसान परिवार से संबंधित हैं, इसलिए वे खुद कृषि में आधुनिकता लाने के लिए काफी गंभीर है।

आधुनिक खेती कर किसान कमाएं मुनाफा

जींद - !- खंड कृषि अधिकारी डॉ. पवन भारद्वाज ने कहा कि आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर किसान खेती से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जरूरत है किसान को जागरूक होने की। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों को लेना चाहिए। डॉ. भारद्वाज गुरुवार को ईगराह गांव में आयोजित एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर में किसानों को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आयोजित शिविर में कृषि अधिकारी डॉ. जयप्रकाश शर्मा, डॉ. कमल सैनी व डॉ. रामप्रकाश ने भी किसानों को आधुनिक खेती के टिप्स दिए।

आदर्श कृषि ग्राम है ईगराह

डॉ. भारद्वाज ने बताया कि योजना के तहत गांव में गेहूं के २० प्रदर्शन प्लांट आधुनिक तकनीक से बिजाई कराए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ईगराह गांव को आदर्श कृषि ग्राम घोषित किया गया है। इस मौके पर डॉ. कमल सैनी ने गेहूं की नवीनतम वैरायटी, उत्पादन पद्धति की जानकारी दी। यूनियन बैंक अधिकारी डॉ. विभोर ने बैंक द्वारा खेती बाडी के लिए दिए जा रहे ऋण की जानकारी दी। कृषि अधिकारी डॉ. जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि गांव में चार किसान प्रशिक्षण शिविर व चार किसान-वैज्ञानिक चर्चा कार्यक्रम होंगे।

छत्तीसगढ में किसानों ने नहीं की खुदकुशी

एनसीआरबी के मुताबिक देश भर में २०११ में १४,००४ किसानों ने आत्महत्या की है। यह संख्या पिछले साल २०१० में हुई १५,९३३ मौत की अपेक्षा कम है। रिपोर्ट कि माने तो पिछले साल छत्तीसगढ में किसी भी किसान ने खुदकुशी नहीं की। जबकि अकेले वर्ष २०१० में छत्तीसगढ के १४१२ किसानों ने आत्महत्या की थी।

जैविक व आधुनिक खेती ने संवारी इन्द्रशरण की तकदीर

भोपाल। खेती सीधी जिले की अधिकतर आबादी की आजीविका का आधार है। यहां की भौगोलिक दुरूहता, लगातार घट रही वर्षा की मात्रा तथा जमीन के अधिक उपजाऊ न होने के कारण किसानों को कठिनाईयों का सामना करना पडता है। सिंचाई के साधन सीमित होने तथा रासायनिक उर्वरक के दिनोंदिन बढते दामों ने उनकी कठिनाईयों को और बढा दिया है। ऐसे कठिन समय में जैविक खेती को अपनाकर तथा खेती के तरीकों को आधुनिक बनाकर ग्राम नौगवां धीर सिंह के किसान इन्द्रशरण सिंह ने खेती से लाखों रूपये कमाये हैं। उन्होंने लगातार चार वर्षों से कम वर्षा के बावजूद वैज्ञानिक तरीके अपनाकर खेती को लाभकारी बनाया है। उनकी सफलता जिले के अन्य किसानों के लिये प्रेरणादायी है।

जिला मुख्यालय सीधी से मात्र १० किलोमीटर की दूरी पर ग्राम नौगवां धीरसिंह स्थित है। यहां वर्ष २००५ में शिक्षित युवा किसान इन्द्रशरण सिंह को सरपंच बनने का अवसर मिला। वाणिज्य तथा इतिहास विषयों में स्नातकोत्तर एवं विधि स्नातक उपाधि प्राप्त श्री सिंह के मन में गांव के विकास की ललक पैदा हुई। पढे-लिखे और सरपंच होने के कारण उन्हें शासन की ग्रामीण विकास की योजनाओं तथा अन्य विभागों की जानकारी मिली। इनका उपयोग उन्होंने गांव के विकास तथा अपनी खेती को उन्नत करने में किया। उन्होंने ग्राम पंचायत भवन के चारों ओर तारबंदी करवाकर ७.५ एकड क्षेत्र में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से फलदार पौधों का रोपण कराया। आज यहां आँवला, अमरूद, आम तथा नीबू के पौधे लहलहा रहे हैं। आम को छोडकर बाकी में फल आने प्रारंभ हो गये हैं। इसकी देखभाल के लिये ग्राम पंचायत ने एक चैकीदार की व्यवस्था की है। इस उद्यमी किसान ने अपनी खेती को आधुनिक बनाने का निश्चय किया। उन्होंने कृषि विभाग से ३८ हजार रूपये अनुदान पर ट्रेक्टर खरीदा। इसके बाद उन्होंने खेती के कई उपकरण ड्रिप सिंचाई सिस्टम तथा स्प्रिंकलर खरीदे। उन्होंने ५ एकड क्षेत्र में मेडागास्कर विधि से धान का रोपण कराया। इससे उन्हें सामान्य से दोगुना उत्पादन प्राप्त हुआ। उन्होंने सहकारी बैंक सीधी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर नियमित लेनदेन प्रारंभ किया।

श्री सिंह ने संभाग के कमिश्नर डॉ. रवीन्द्र पस्तोर के किसानों को बीज आत्मनिर्भरता के लिये चलाये जा रहे अभियान से जुडकर अवंतिका बीज उत्पादक सहकारी समिति गठित की। इसके सदस्यों ने गत वर्ष ४०० क्विंटल गेहूँ का आधार बीज तैयार किया। इसमें से २०० क्विंटल स्वयं के उपयोग के लिये रखकर शेष २०० क्विंटल कृषि विभाग के माध्यम से जिले के किसानों को बेचा गया। खेती को लाभकारी बनाने के लिये श्री सिंह ने जैविक खेती को अपनाया। उन्होंने गोबर गैस संयंत्र, नाडेप टांका तथा ५० फुट लम्बा बर्मीपिट बनवाया। इनसे हर महीने तीन क्विंटल जैविक खाद प्राप्त होती है।

कृषक इन्द्रशरण ने परम्परागत खेती को आधुनिक बनाने के साथ फल तथा सब्जी उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने उद्यानिकी विभाग के सहयोग से १८ लाख रूपये की लागत से फलदार पौधों की माडल नर्सरी तैयार की। इसमें आम, नीबू, कटहल, आँवला तथा अमरूद के चार लाख पौधे तैयार किये गये। उन्होंने अपने घर के आसपास तथा खेत की मेडों में १५०० से अधिक सागौन के पेड तैयार किये हैं। पपीता, नीबू तथा अमरूद वे सफलतापूर्वक उगा रहे हैं। उन्होंने १० एकड क्षेत्र में सब्जी का उत्पादन प्रारंभ किया है। इसमें २५० वर्गमीटर का ग्रीनहाउस बनाया गया है, जिसमें सब्जी तथा फलों की पौध तैयार की जायेगी। नलकूप तथा नाले से सिंचाई की व्यवस्था करके पूरे खेत में ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई की जा रही है। खेत में मूली, बैगन, टमाटर, गोभी, धनिया, मिर्च तथा लौकी का उत्पादन हो रहा है। इससे हर माह लगभग ८ हजार रूपये आमदनी होती है। श्री सिंह ने इस साल विभिन्न फसलों से तीन लाख रूपये से अधिक की आमदनी प्राप्त की है। उनका खेत किसानों के लिये प्रेरणा का केन्द्र बन गया है।

किसानों की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार

भारतीय किसान की तस्वीर आज भी कमोबेश कक्षा आठ में लिखे जाने वाले उस निबंध से बाहर नहीं निकल पाई है, जहां हम पहली लाइन में तो यह लिखते थे कि किसान देश का पेट पालते हैं, लेकिन आखिरी लाइन यही रहती थी कि किसान किसानी से इतना कमा नहीं पाते कि वे अपना पेट पाल सकें। भारतीय किसान की यह तस्वीर बदलती क्यों नहीं है? जीवन के हर हर क्षेत्रों में हमने बदलाव देखा और स्वीकारा भी, लेकिन खेती में होने वाले बदलावों को स्वीकारना कभी हमारी प्राथमिकता में क्यों नहीं आता? वर्षों पहले ऑस्ट्रेलिया हमसे मुट्ठी भर दाल सैंपल के तौर पर ले गया और आज दलहन का सबसे बडा निर्यातक बन गया। लेकिन हम आज भी खेती को पारंपरिकता से जोडे रखने में गौरव महसूस करते हैं। विश्व ग्लोबल विलेज में बदल रहा है और इस बदलाव को कृषि में महसूस करने की जरूरत है। अन्न को लेकर हमें भले भी काफी भावनात्मक रहते हैं, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि गेहूं के उत्पादन में हमें जो पहली ऐतिहासिक सफलता मिली, वह बौने मैक्सिकन बीजों के इस्तेमाल से मिली। इसी प्रकार धान की उपज में आइआरआरआइ बीजों (जैसे कि आइआर-८, आइआर-६४ आदि) के द्वारा क्रांति आई जो फिलिपींस से आए थे। बाद में हमने आयातित किस्मों को अपनी देसी किस्मों के साथ मिलाकर विकसित किया और हमने देश में ही उच्च उपज देने वाले बीज तैयार कर लिए।

वास्तव में भारत की खाद्य सुरक्षा और स्वावलंबन की कहानी कहीं अकेले में बैठकर नहीं लिखी गई, बल्कि ऐसा इसलिए संभव हुआ, क्योंकि कई अन्य देशों से बीजों की विभिन्न किस्में यहां आई। कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों और भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने इस विषय पर काम किया, उन्होंने अपनी सर्वोत्कृष्ट सामग्री को संयोजित किया। कुछ पाया तो कुछ खोया भी इसमें कोई शक नहीं है कि १९७० और १९८० के दशकों में हमने खाद्यान्न उत्पादन में जो जबरदस्त तर१की की है, उससे हममें खाद्य सुरक्षा का भाव जागा है। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए स्थिति संतोषजनक नहीं लगती। भारत की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आइसीआरआइईआर) के एक कार्य-पत्र के मुताबिक, वर्ष २०२० तक भारत को अपनी पैदावार दोगुनी करनी होगी। मांस, मछली और अंडों के लिए मांग में २.८ गुना वृद्धि हो जाएगी। अनाज के लिए मांग में दोगुना इजाफा होगा। फलों और सब्जियों के लिए मांग में १.८ गुना की बढोतरी का अनुमान है और दूध की मांग २.६ गुना होने की अपेक्षा है। ये सभी अनुमान वर्ष २००७ की मांग पर आधारित हैं। मांग में इस प्रगति के चलते अगले १० से १५ सालों में भूमि तथा जल संसाधनों पर और ज्यादा दबाव पडेगा। अगर कपास को छोड दें तो वर्ष १९९१ और २००७ के बीच भारत में अन्य सभी फसलों की पैदावार स्थिर रही।

कृषि मंत्रालय के आंकडे यह जाहिर करते हैं कि इस अवधि में गेहूं, धान, दालों, सोयाबीन और गन्ने की उपज में वृद्धि मात्र ०.१९ प्रतिशत से लेकर १.४ प्रतिशत सालाना रही है। हालांकि इसी दौरान कपास की पैदावार ४.३८ प्रतिशत सालाना की दर से बढी है, जो वास्तव में यह दर्शाती है कि जीएम तकनीक की बदौलत कितनी तर१की हुई है। अब तक बीटी कॉटन ही ऐसी एकमात्र जीएम फसल है, जिसे भारत में खेती के लिए मंजूरी दी गई है और इस किस्म ने भारतीय किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचाया है। आज करीब ५८ लाख भारतीय कपास किसान ढाई करोड एकड से ज्यादा जमीन पर बीटी कॉटन उगा रहे हैं। साल २००२ में इस तकनीक के भारत में इस्तेमाल शुरू किए जाने के बाद से कपास का उत्पादन दोगुना हो चुका है। कभी भारत कपास को आयात किया करता था। आज यह दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बडा उत्पादक और निर्यातक है। बीटी कॉटन से उत्पाद बढा और कीटनाशकों की खपत कम हुई। इन दोनों पहलुओं के चलते किसानों की आमदनी में लगभग ३१,५०० करोड रुपये का इजाफा हुआ है। यह एक अभूतपूर्व सफलता है, जो इस तकनीक के अमल में आने के बाद मात्र सात सालों में प्राप्त की गई है। इससे साबित होता है कि किसानों ने इस प्रौद्योगिकी को स्वीकार किया है और उनका अनुभव बेहद अच्छा रहा है। खाद्य की उपलब्धता को बढाने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक यह है कि देश में भूमि और जल की उत्पादकता को बढाया जाए। औद्योगिकरण का दबाव, कृषि योग्य भूमि की कमी और घटते जल स्तर के चलते यह काम सरल प्रतीत नहीं होता। हालांकि कृषि के तौर तरीकों और उपज में सुधार के जरिये इस समस्या से निपटने के बेहतरीन मौके हमारे पास हैं।

अनुमान है कि बेहतर कृषि विधियों से पैदावार को ५० प्रतिशत तक बढाया जा सकता है, जबकि फसल सुधार के द्वारा उपज में ५० प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि की जा सकती है। आपूर्ति श्रृंखला में कम बर्बादी, जमीन, पानी, लवणीय मिट्टी की बढी उत्पादकता, कृषि विधियों और फसल में सुधार आदि इन सभी उपायों को एक पैकेज के तौर पर प्रयोग करना होगा, तभी अगले २५ से ४० सालों में हम अपनी बढती आबादी के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध करा सकेंगे। इनमें से किसी भी एक तरीके के दम पर पूर्ण सफलता हासिल नहीं की जा सकती। हमें बॉयो टेक्नोलॉजी को भी अपनाना पडेगा। पारंपरिक तरीकों को बाय-बाय लोगों में एक गलत धारणा फैली हुई है कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ सिर्फ आनुवांशिक संशोधन है। यह सही नहीं है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी की कई विशेषताएं और तकनीकें होती हैं, जिनमें से आनुवांशिक संशोधन सबसे मशहूर टेक्नोलॉजी है। आणविक चिह्नक आधारित चयन वह साधन है, जो भारत और विदेशों में व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाता है। इससे पादप प्रजनन की गति और शुद्धता में वृद्धि की जाती है। इसके अलावा और भी कई जैव तकनीकी साधन हैं, जिनका इस्तेमाल पादप प्रजनन के लिए काफी किया जाता है। जैसे कि डिहाप्लॉयड्स, ट्रिशू कल्चर आदि। बीटी से परहेज क्यों आनुवांशिक रूप से से उन्नत बीज सबसे पहले १९९६ में दुनिया में पेश किए गए थे।

वर्ष २०१० में २९ देशों के १ करोड ५४ लाख किसानों ने १४ करोड ८० लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बॉयोटेक फसलों को बोया, ९० प्रतिशत यानी १ करोड ४४ लाख किसान विकासशील देशों के गरीब तथा अल्प-संसाधन युक्त किसान थे। यह हिस्सेदारी पिछले ५ सालों से बेहद तेजी से बढ रही है, जीएम फसलों की स्वीकृति का स्तर काफी ऊपर पहुंच चुका है। जीएम की दो किस्म की विशेषताएं होती हैं। वे हैं इनपुट ट्रेट्स और आउटपुट ट्रेट्स। इनपुट ट्रेट्स वे होते हैं, जो पौधे में एक गुण डालते हैं। इसकी वजह से फसल में जो चीजें डाली जाती हैं, वे बदल जाती हैं। इससे सबसे पहला फायदा किसान को होता है। इसका एक उदाहरण है कीटों को सहन करने की क्षमता (बीटी), जिससे पौधे को ऐसी शक्ति मिलती है कि वह फसलों पर हमला करने वाले कीटों का मुकाबला कर पाता है। इस विशेषता से फसलों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों के प्रयुक्त होने का तरीका बदल जाता है। अन्य उदाहरण है खरपतवार सहने की क्षमता, जो खरपतवार के इस्तेमाल के तरीके को बदल देती है। अब तक केवल बीटी कॉटन ऐसी जीएम फसल है, जिसे भारत में खेती की अनुमति मिली है। मैंने पहले भी कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता प्रवेश कर रही है। परंपरा के मोह में हम आधुनिकता का विरोध करते हैं, लेकिन हमारी जीवनशैली ऐसी हो गई है कि विरोध के बाद भी आधुनिकता चुपके से हमारे साथ हो लेती है। कृषि को भी हमें इसी तरीके से देखना होगा। बदलाव को महसूस करते हुए नई तकनीकि और प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा, तभी भारतीय किसान की तस्वीर भी बदलेगी और किसान देश का पेट पालने के साथ-साथ अपना पेट भी पाल सकेंगे

प्राकृतिक खेती से पटखनी खाती आधुनिक खेती

रासायनिक खेती करके हम समाज में जहर का अनाज फैला रहें हैं और जहर की सब्जियां फैलाईं।

इसके परिणामस्वरूप समाज के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के उपर नकारात्मक असर हुआ। यानि श्रम शक्ति का ह्रास हुआ। ऐसे में कैसे विकास की ओर जाएंगे। श्रम शक्ति को ह्रास से बचाने के लिए अच्छा अनाज चाहिए। ऐसा अनाज जो हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करे।

सुभाष शर्मा ने रासायनिक खाद, जहरीली दवाईयां और बाहर से बीज लाकर खेती प्रारंभ की थी। परिश्रम करने की मन में अत्यंत इच्छा थी। परिश्रम के बल पर खेती से बहुत उत्पाद निकाले। उन्हें लगा कि मैंने साइंस को अच्छी तरह समझ लिया है और अब मैं इससे बहुत तेजी से प्रगति करूंगा। इसके बाद उनके खेतों में जो उत्पादन होता था, उसमें गिरावट होने लगी। कपास उत्पादन जो १२ क्विंटल था, वह तीन क्विंटल पर आ गया। जो वार २० क्विंटल उपजता था वह पांच क्विंटल पर आ गया। सब्जियां ३०० क्विंटल उपजती थीं, वह घटकर ५० क्विंटल रह गईं। जब उत्पाद इतने नीचे आ गये तो उनका परिश्रम व्यर्थ जाने लगा। परिश्रम के बावजूद ऊपर कर्ज का बोझ बढता जा रहा था। उन्हें लगने लगा कि कहीं न कहीं मेरे तरीके में खोट है। इसके बाद नए तरह के विज्ञान के तहत नैसर्गिक खेती की। तब समझ में आया कि खेतों में उत्पादन क्यों घट रहा था।

असल में रासायनिक खाद इस्तेमाल करने की वजह से खेत के जीवाणुओं का विनाश हो रहा था। रासायनिक खेती करके मैंने समाज में जहर का अनाज फैलाया और जहर की सब्जियां फैलायी। इसके परिणामस्वरूप समाज के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के उपर नकारात्मक असर हुआ। यानि श्रम शक्ति का ह्रास हुआ। ऐसे में कैसे विकास की ओर जाएंगे। श्रम शक्ति को ह्रास से बचाने के लिए अच्छा अनाज चाहिए। ऐसा अनाज जो हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करे। आज किसान और किसानी दोनों बहुत तकलीफ में है, क्योंकि सरकारी नीतियां उसके अनुकूल नहीं हैं। सरकारी नीतियों को समझना भी किसानों के लिए अनिवार्य हो गया है। इन नीतियों की वजह से देश की श्रमशक्ति पर काफी नकारात्मक असर पड रहा है। ऐसे में भला हमारी कृषि कैसे विकास की ओर जाएगी।

बढता हुआ तापमान हमारे देश की उत्पादकता को प्रभावित कर रहा है। लाखो प्रकार की प्रजातियां और वनस्पतियां इस बढते हुए तापमान की वजह से नष्ट हो रही हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पेड को बच्चे जैसा पालना शुरू किया। अब अपनी खेती में जहर विज्ञान का प्रयोग नहीं करूंगा और फिर प्रगति के विज्ञान की ओर पदार्पण किया। जब से मैंने नैसर्गिक खेती आरंभ की है तब से मेरी मिट्टी और पानी की हालत सुधरने लगी है। खेती से तीन प्रकार का स्वावलंबन प्राप्त हुआ। पहला जमीन का स्वावलंबन। इस स्वावलंबन के कारण किसी भी प्रकार का कोई कीट नियंत्रण नहीं करना पडता। कोई भी खाद खेती में बाहर से लाकर नहीं डालनी पडती। ये सारा सिस्टम प्रकृति की मदद से खडा किया गया। गाय का गोबर सर्वोत्तम खाद है। जब कृषि में वृक्षों का नियोजन किया तो खेत का तापमान नियंत्रण में आने लगा और कई प्रकार के जीव-जीवाणुओं ने उत्पादकता बढाने का काम किया। जब पेड बढे तो खेत में पक्षियों का आगमन बढा। उन पक्षियों ने खेतों में कीट नियंत्रण का काम किया तो उनके प्रति प्रेम और बढ गया। फिर तो पक्षियों के लिए आम, जामुन और गूलर के पेड लगाए। जो पेड पक्षियों को पसंद हैं उन पेडों की संख्या खेत में यादा होनी चाहिए।

वे पेड ग्रीष्म में भी पूरे हरे-भरे रहते हैं। हरे हैं तो यहां के तापमान को वे झेल रहे हैं। वे कार्बन डाइआक्साइड खींच रहे हैं। वृक्षों के कारण कीट-नियंत्रण तो हुआ ही, साथ ही उन पर बैठने वाले पक्षियों के मल से खेतों की उत्पादकता भी बढी। नैसर्गिक खेती करते हुए एक बात और समझ में आई कि खेती से निकलने वाले सभी अवशेषों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस सोच के साथ फसलों से निकलने वाली घास के पुनःउपयोग का तरीका प्रारंभ किया। इसके जरिए खेतों को बायोमास मिलने लगा। जिसकी वजह से खेती को काफी फायदा पहुंचा। ये प्रयोग देश के अन्य हिस्सों के किसानों को भी अपने-अपने यहां करना चाहिए ताकि खेती को एक नया आयाम मिल सके।

खेती की पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जाए। कृषि के तंत्र ज्ञान को समझ लेना बहुत जरूरी है। हमें यह जानना होगा कि इसमें कैसे खाद पैदा की जा सकती है। कैसे इसमें कीट-नियंत्रण का काम प्रभावी रूप से होता है। खेतों में जब बायोमास बढा, तापमान नियंत्रित हुआ तो फिर धीमे-धीमे केंचुए पैदा होने लगे। इनसे खेती को बडा लाभ हुआ। केंचुए भी भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हर जीव की रक्षा होनी जरूरी है। क्योंकि भारत के विकास में इनका अमूल्य योगदान है। एक स्क्वायर फीट में यदि छः केंचुए हैं तो इसका मतलब हुआ एक एकड मे ढाई लाख केंचुए। एक केंचुआ कम से कम अपने जीवन चक्र में १० से ४० छिद्र करता है। इससे खेतों को भरपूर पानी मिलना शुरू हुआ। पानी जब गया तो आक्सीजन भी गया और जमीन के अन्दर के जीवों की सजीव व्यवस्था कायम हुई। केंचुए की वजह से चींटियों का आना शुरू हुआ। फिर दीमक हुए और कई अन्य प्रकार के जीवों का विस्तार हुआ। इस तरह नैसर्गिक खेती के कारण जमीन फिर से सजीव हो गई। आज हम मृत जमीन में खेती कर रहे हैं। जिस जमीन में जीव नहीं हैं वह जमीन मृत है। वह मृत जमीन पेट नहीं भर सकती। वो बर्बाद ही करेगी। तो इस जमीन को सजीव करने के लिए हमें प्रकृति से मदद लेनी होगी।

पानी के स्वावलंबन के तहत खेत में गिरने वाले पानी को रोकने की प्रक्रिया का निर्माण किया। फसलों की बुआई जीरो लेवल पर करने की प्रणाली विकसित की। बहुत यादा बारिस होने पर यह पानी बह जाता था। इस अतिरिक्त पानी को रोकने की दिशा में भी मैंने काम किया। एक हेक्टेयर के पीछे बीस फुट लम्बा, १० फुट चौडा और १० फुट गहरे गड्ढे का निर्माण किया गया। उस गड्ढे में अतिरिक्त पानी रुकने लगा। इससे भूमि को सिंचाई की जरूरत कम हुई। अगर देश के किसान चाहते हैं तो उन्हें रासायनिक खेती छोड अपनी पारंपरिक नैसर्गिक खेती की ओर लौटना होगा।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति-२०१३

भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विज्ञान एवं तकनीक द्वारा ग्रामीण और कृषि विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी लगभग ६५ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है इसलिए उनके जीवन स्तर में सुधार मुख्य रूप से कृषि एवं उत्पादन में वृद्धि पर निर्भर करता है। डॉ. सिंह ने कहा कि देश में खाद्य सुरक्षा के लिए १२वीं पंचवर्षीय योजना काल में ४ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सतत् कृषि विकास दर आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जल और खेती योग्य भूमि की कमी से विकास दर पर विपरीत प्रभाव पडता है। उन्होंने खेती में जल संरक्षण तकनीकों, भूमि उत्पादकता में वृद्धि और जलवायु अनुरूप किस्मों के विकास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी लोक नीतियों के साथ-साथ विज्ञान एवं तकनीकी नीतियों के लिए कृषि में परिवर्तन मुख्य प्राथमिकता के स्तर पर होना चाहिए। श्री सिंह ने 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति-२०१३' का विमोचन किया जिसमें कृषि अनुसंधान पर भी प्रकाश डाला गया है।

'कृषि के लिए अनुसंधान एवं विकास नीति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रणाली तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति के साथ कृषि अनुसंधान एवं विकास नीति को एक साथ लाया जाएगा।'

किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा - सोमपाल शास्त्री

स्वतंत्रता इस मूल अवधारणा पर आधारित है कि व्यक्ति अपनी भावना को सही अभिव्यक्ति दे सके और अपनी आजीविका को सुचारु रूप से चला सके। धर्म की अवधारणा भी इसी पर आधारित है कि किसी और के काम में हस्तक्षेप किए बिना व्यक्ति अपना कर्तव्य स्वतंत्रतापूर्वक करे। इस नजरिए से समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति के वैधानिक अधिकार की रक्षा करना शासक का कर्तव्य हो जाता है।

लोकतंत्र में वैधानिक अधिकारों की रक्षा इसलिए सुनिश्चित मानी जाती है क्योंकि सरकार किसको बनाना है यह जनता ही तय करती है। पर आजाद भारत में देखें तो किसानों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। वह शासकीय तंत्र का गुलाम बनकर रह गया है। किसान खुद अपनी जमीन के मालिक नहीं हैं, जिससे उन्हें हर तरह के शोषण का सामना करना पडता है। उन्हें हर छः महीने पर जमाबंदी रिकॉर्ड जमा कराना होता है, तो दूसरी तरफ कर भी देना होता है। यह व्यवस्था उपनिवेशवादी शासकों ने लागू की थी। तब से लेकर आज तक यह व्यवस्था कायम है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान मनमाफिक तरीके से अपनी संपत्ति नहीं बेच सकते।

वहीं देखिए तो जमीन पर मालिकाना हक नहीं होने के साथ-साथ अपने उत्पादों को अपनी मर्जी से जहाँ चाहें वहाँ बेचने का अधिकार भी उनके पास नहीं है। उसके उत्पादन की बोली कोई और लगाता है। मध्यप्रदेश की व्यापारिक राजधानी माने जाने वाले इंदौर की मंडी में आप जाइए तो वहाँ छोटा किसान जो सिर पर एक टोकरी में गोभी या टमाटर भरकर मंडी लाता है वह स्वयं नहीं तय करता कि उसकी गोभी या टमाटर किस भाव में बेचे जाएँगे। उस पर अढाती पहले उसकी टोकरी से दो-चार गोभी या एक-दो किलो टमाटर निकाल लेता है, जिस पर वह अपना अधिकार समझता है।

फिर चार से आठ प्रतिशत तक अढाती ली जाती है, जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट की अवहेलना होती है। वैधानिक तौर पर मंडी कर के अलावा किसानों से कोई और कर नहीं लिया जा सकता पर अढाती इतने मनमौजी कि वे खुलेआम किसानों से कर लेते हैं। यह सब प्रशासन की नाक के नीचे होता है पर इसकी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ किसान यदि अपने इलाके की मंडी छोडकर दूसरी मंडी में अपना उत्पाद बेचना चाहे तो उसे परमिट की जरूरत पडती है। मैंने मध्यप्रदेश में इस व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की पर सरकार ने उस ओर दिलचस्पी नहीं दिखाई। साहूकारों के हाथों का खिलौना बनना किसानों की मजबूरी है। किसान यदि ट्रैक्टर, जनरेटर, थ्रेसर खरीदने, पशु खरीदने या किसी अन्य वजहों से बैंकों से कर्ज लेना चाहे तो उसके लिए इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पडता है कि किसानों को साहूकारों से अधिक सूद अदा करने की कीमत पर कर्ज लेना ज्यादा मुनासिब लगता है। मैं ऐसे कई किसानों से मिला हूँ जिन्हें ट्रैक्टर खरीदने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पडी।

ये मूलभूत बातें हैं, जो किसानों को आजाद भारत में भी गुलाम बना देती हैं। किसानों की जमीनों पर अधिग्रहण करना सरकार के लिए सबसे आसान है। वह जब चाहे किसानों से जमीन लेकर उद्योगपतियों और पूँजीपतियों को बेच सकती है। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि किसानों की भूमि सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिग्रहीत की जाए, पर उद्योगपतियों को जमीनें निजी उपयोग के लिए धडल्ले से दी जाती हैं। अधिग्रहण के समय किए गए वादे तक किसानों से पूरे नहीं किए जाते। वास्तव में उन्हें जो मूल्य प्राप्त होता है वह वास्तविकता से बहुत कम होता है। मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्रति एकड जमीन २५-२६ लाख रुपए औसत मूल्य तय किया था, पर किसानों को महज १ लाख ७३ हजार रु. प्रति एकड मूल्य दिया गया। किसानों के लिए सरकार का यह दोहरा मानदंड है या नहीं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनका आत्मविश्वास बढाने के लिए यह जरूरी है कि गाँवों में बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ। गाँवों में बिजली पहुँचे, सडक बने, सिंचाई की सुविधाएँ बढें तो किसानों को खेती करना आसान रहेगा। तो दूसरी तरफ खेती के अलावा उनका तकनीकी ज्ञान और कौशल भी बढाना चाहिए, जिससे कि वे वैकल्पिक रोजगारों पर भी विचार करें। जब तक किसानों का हाथ मजबूत नहीं होगा देश की बेतहाशा बढ रही जनसंख्या की भूख मिटाने के लिए खेतों और किसानों पर पडने वाले दबाव को झेलना मुश्किल होगा।

(लेखक राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष, मप्र योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, केंद्रीय योजना आयोग के और १२वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं)

गांवों में भी गूंजती रहें किलकारियां

भारत की एक बहुत बडी आबादी गांवों में रहती है. आज भी भारत के अधिकतर गांव सुविधाहीन और अभावग्रस्त हैं. इन गांवों में अकसर हमें अस्पतालों की कमी नजर आती है लेकिन सरकार द्वारा समय-समय पर उठाए गए कदमों की वजह से आज गांवों में भी खुशहाली है. यूं तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें तो सरकार ने गांव की महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना है जननी सुरक्षा योजना. इस योजना को शुरू करने का सरकार का सबसे बडा मकसद शिशु मृत्यु दर को कम करना है. गांवों में अकसर घर में प्रसव होने के कारण सबसे ज्यादा शिशुओं की मौत होती है और कभी-कभी तो महिलाओं की भी मौत हो जाती है. इसलिए सरकार यह चाहती है कि वो इस योजना के द्वारा इन दोनों के मृत्यु दर में कमी ला सके .

पहले की दशा - बात छत्तीसगढ गांव की है. जहां के अधिकतर घरों में पुरुष बाहर कमाने चले जाते थे और गांव में रह जाती थीं उनकी गर्भवती पत्नियां. कई बार अकेलेपन और गरीबी की वजह से यहां बडी संख्या में गर्भवती महिलाओं मिसकैरेज हो जाता था या कई बार तो ऐसा होता था कि बच्चा जन्म के बाद भी गरीबी या बीमारी के कारण मौत के मुंह में चला जाता था और उसकी मां कुछ भी नहीं कर पाती थी. ऐसे समय में इन्हें एक ऐसी सहायता चाहिए होती है जो इन्हें आर्थिक और भावनात्मक स्तर पर मदद कर सके. सरकार भावनात्माक स्तर पर तो इनकी मदद नहीं कर सकती लेकिन सरकार ने आर्थिक स्तर पर इनकी मदद करने का अच्छा उपाय किया है.

अब की दशा - सरकार द्वारा शुरू किए गए जननी सुरक्षा योजना की वजह से आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ रही है. ग्रामीण जननी सुरक्षा योजना का ही नतीजा है कि पिछले पांच वर्षों में भारत में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव की संख्या लगभग ढाई गुना हो गई है. अगर हम छत्तीसगढ की बात करें तो संस्थागत प्रसव को बढावा देने के लिए वर्ष २००५ में छत्तीसगढ में जननी सुरक्षा योजना लागू की गई थी. तब राज्य में संस्थागत प्रसव की संख्या केवल २३.५५ प्रतिशत थी, जो वर्ष २०११-१२ में बढकर ५९.६० प्रतिशत हो गई. बीते वित्तीय वर्ष में अप्रैल ११ से लेकर मार्च २०१२ तक छत्तीसगढ में कुल पांच लाख ६५ हजार प्रसव हुए, जिनमें से तीन लाख ३७ हजार २८ गर्भवती माताओं ने अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराया, जो निर्धारित लक्ष्य का ५९.६० प्रतिशत है. अस्पताल में प्रसव कराने वाली महिलाओं को २२ करोड २४ लाख ५४ हजार रूपए से अधिक की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी गई. इसके साथ गर्भवती माताओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने पर स्वास्थ्य मितानिनों को एक करोड दस लाख ५८ हजार रूपए का भुगतान किया गया है.

आखिर क्या है जननी सुरक्षा योजना - जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात आयाओं और आशा बहनों द्वारा अस्पताल में प्रसव कराने के लिए गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें प्रसव के लिए अस्पताल ले जाया जाता है. गर्भवती माताएं स्वयं भी प्रसव के लिए सीधे अस्पताल जा सकती हैं. इसके अलावा गर्भवती माताएं अस्पताल जाने के लिए टोल फ्री नम्बर १०८ डायल कर ११०८ संजीवनी एक्सप्रेस१ का एम्बुलेंस भी बुला सकती हैं. यह निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है. इसके साथ ही किराए के वाहन का उपयोग किए जाने की स्थिति में अस्पताल पहुंचने पर उन्हें चार सौ रुपए परिवहन खर्च दिया जाता है. अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिला को एक हजार ४०० रुपए तथा शहरी महिला को एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इसी प्रकार यदि ग्रामीण महिला मितानिनों की देखरेख में अपने घर में प्रसव कराती है, तो उसे पांच सौ रुपए की राशि दी जाती है.

जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत २००१ में हुई थी. इसका उद्देश्य मातृत्व और शिशु मृत्यु दर को कम करना है. इसकी एक खूबी यह भी है कि यह योजना पूर्ण रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है. साथ ही यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में १९ वर्ष से अधिक आयु की सभी गर्भवती महिलाओं को दो बच्चों के जन्म तक ही ये सुविधा देती है.

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक महिलाओं के पास एमसीएच कार्ड के साथ-साथ जननी सुरक्षा योजना कार्ड भी होना जरूरी है तभी वो आसानी से इस योजना का लाभ उठा पाएंगी .

माना कि आज अधिकतर महिलाओं को इस योजना की जानकारी नहीं है पर स्वास्थ्य संगठनों की वजह से आज इस योजना का फायदा बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं उठा रही हैं और सरकार की ये कोशिश है कि इस योजना का फायदा वो ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण और शहरी महिलाओं को दिला सके जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं.

अंगूर की आधुनिक खेती

अंगूर संसार के उपोष्ण कटिबंध के फलों में विशेष महत्व रखता है। हमारे देश में लगभग ६२० ई.पूर्व ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अंगूर की व्यवसायिक खेती एक लाभकारी उद्यम के रूप में विकसित हो गई थी लेकिन उत्तरी भारत में व्यवसायिक उत्पादन धीरे - धीरे बहुत देर से शुरू हुआ। आज अंगूर ने उत्तर भारत में भी एक महत्वपूर्ण फल के रूप में अपना स्थान बना लिया है और इन क्षेत्रों में इसका क्षेत्रफल काफी तेजी से बढता जा रहा है। पिछले तीन दशकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंगूर कि खेती ने प्रगति की है जिसके फलस्वरूप भारत में अंगूर के उत्पादन, उत्पादकता एवं क्षेत्रफल में अपेक्षा से अधिक वृद्धि होती जा रही है।

उपयोग - अंगूर एक स्वादिष्ट फल है। भारत में अंगूर अधिकतर ताजा ही खाया जाता है वैसे अंगूर के कई उपयोग हैं। इससे किशमिश, रस एवं मदिरा भी बनाई जाती है।

मिट्टी एवं जलवायु - अंगूर की जड की संरचना काफी मजबूत होती है। अतः यह कंकरीली,रेतीली से चिकनी तथा उथली से लेकर गहरी मिट्टियों में सफलतापूर्वक पनपता है लेकिन रेतीली, दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास अच्छा हो अंगूर की खेती के लिए उचित पाई गयी है। अधिक चिकनी मिट्टी में इसकी खेती न करे तो बेहतर है। अंगूर लवणता के प्रति कुछ हद तक सहिष्णु है। जलवायु का फल के विकास तथा पके हुए अंगूर की बनावट और गुणों पर काफी असर पडता है। इसकी खेती के लिए गर्म, शुष्क, तथा दीर्घ ग्रीष्म ऋतू अनुकूल रहती है। अंगूर के पकते समय वर्षा या बादल का होना बहुत ही हानिकारक है। इससे दाने फट जाते हैं और फलों की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पडता है। अतः उत्तर भारत में शीघ्र पकने वाली किस्मों की सिफारिश की जाती है।

किस्में - उत्तर भारत में लगाई जाने वाली कुछ किस्मों की विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं।

परलेट - यह उत्तर भारत में शीघ्र पकने वाली किस्मों में से एक है। इसकी बेल अधिक फलदायी तथा ओजस्वी होती है। गुच्छे माध्यम, बडे तथा गठीले होते हैं एवं फल सफेदी लिए हरे तथा गोलाकार होते हैं। फलों में १८ - १९ तक घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं। गुच्छों में छोटे - छोटे अविकसित फलों का होना इस किस्म की मुख्य समस्या है।

ब्यूटी सीडलेस - यह वर्षा के आगमन से पूर्व मई के अंत तक पकने वाली किस्म है गुच्छे मध्यम से बडे लम्बे तथा गठीले होते हैं। फल मध्यम आकर के गोलाकार बीज रहित एवं काले होते हैं। जिनमे लगभग १७ - १८ घुलनशील ठोस तत्त्व पाए जाते हैं।

पूसा सीडलेस - इस किस्म के कई गुण 'थाम्पसन सीडलेस' किस्म से मेल खाते हैं। यह जून के तीसरे सप्ताह तक पकना शुरू होती है। गुच्छे मध्यम, लम्बे, बेलनाकार सुगन्धयुक्त एवं गठे हुए होते हैं। फल छोटे एवं अंडाकार होते हैं। पकने पर हरे पीले सुनहरे हो जाते हैं। फल खाने के अतिरिक्त अच्छी किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त है।

पूसा नवरंग -यह संकर किस्म भी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकसित की गयी है। यह शीघ्र पकने वाली काफी उपज देने वाली किस्म है। गुच्छे मध्यम आकर के होते हैं। फल बीजरहित, गोलाकार एवं काले रंग के होते हैं। इस किस्म में गुच्छा भी लाल रंग का होता है। यह किस्म रस एवं मदिरा बनाने के लिए उपयुक्त है।

प्रवर्धन - अंगूर का प्रवर्धन मुख्यतः कटिंग कलम द्वारा होता है। जनवरी माह में काट छाँट से निकली टहनियों से कलमे ली जाती हैं। कलमे सदैव स्वस्थ एवं परिपक्व टहनियों से लिए जाने चाहिए। सामान्यतः ४ - ६ गांठों वाली २३ - ४५ से.मी. लम्बी कलमें ली जाती हैं।कलम बनाते समय यह ध्यान रखें कि कलम का निचे का कट गांठ के ठीक नीचे होना चाहिए एवं ऊपर का कट तिरछा होना चाहिए। इन कलमों को अच्छी प्रकार से तैयार की गयी तथा सतह से ऊँची क्यारियों में लगा देते हैं। एक वर्ष पुरानी जडयुक्त कलमों को जनवरी माह में नर्सरी से निकल कर खेत में रोपित कर देते हैं।

बेलों की रोपाई - रोपाई से पूर्व मिट्टी की जाँच अवश्य करवा लें। खेत को भलीभांति तैयार कर लें। बेल की बीच की दुरी किस्म विशेष एवं साधने की पद्धति पर निर्भर करती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रख कर ९० ट ९० से.मी. आकर के गड्ढे खोदने के बाद उन्हें १/२ भाग मिट्टी, १/२ भाग गोबर की सडी हुई खाद एवं ३० ग्राम क्लोरिपाईरीफास, १ कि.ग्रा. सुपर फास्फेट व ५०० ग्राम पोटेशीयम सल्फेट आदि को अच्छी तरह मिलाकर भर दें। जनवरी माह में इन गड्ढों में १ साल पुरानी जडवाली कलमों को लगा दें। बेल लगाने के तुंरत बाद पानी आवश्यक है।

बेलों की सधाई एवं छंटाई - बेलों से लगातार अच्छी फसल लेने के लिए एवं उचित आकर देने के लिए साधना एवं काट - छाँट की सिफारिश की जाती है। बेल को उचित आकर देने के लिए इसके अनचाहे भाग के काटने को साधना कहते हैं, एवं बेल में फल लगने वाली शाखाओं को सामान्य रूप से वितरण हेतु किसी भी हिस्से की छंटनी को छंटाई कहतें हैं।

अंगूर की बेल साधने हेतु पण्डाल, बाबर, टेलीफोन, निफिन एवं हैड आदि पद्धतियाँ प्रचलित हैं। लेकिन व्यवसायिक इतर पर पण्डाल पद्धति ही अधिक उपयोगी सिद्ध हुयी है। पण्डाल पद्धति द्वारा बेलों को साधने हेतु २.१ - २.५ मीटर ऊँचाई पर कंक्रीट के खंभों के सहारे लगी तारों के जाल पर बेलों को फैलाया जाता है। जाल तक पहुँचने के लिए केवल एक ही ताना बना दिया जाता है। तारों के जाल पर पहुँचने पर ताने को काट दिया जाता है ताकि पार्श्व शाखाएँ उग आयें।उगी हुई प्राथमिक शाखाओं पर सभी दिशाओं में ६० सेमी दूसरी पार्श्व शाखाओं के रूप में विकसित किया जाता है। इस तरह द्वितीयक शाखाओं से ८ - १० तृतीयक शाखाएँ विकसित होंगी इन्ही शाखाओं पर फल लगते हैं।

छंटाई - बेलों से लगातार एवं अच्छी फसल लेने के लिए उनकी उचित समय पर काट - छाँट अति आवश्यक है। छंटाई कब करें : जब बेल सुसुप्त अवस्था में हो तो छंटाई की जा सकती है, परन्तु कोंपले फूटने से पहले प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। सामान्यतः काट - छांट जनवरी माह में की जाती है।

कितनी छंटाई करें - छंटाई की प्रक्रिया में बेल के जिस भाग में फल लगें हों, उसके बढे हुए भाग को कुछ हद तक काट देते हैं। यह किस्म विशेष पर निर्भर करता है। किस्म के अनुसार कुछ स्पर को केवल एक अथवा दो आँख छोडकर शेष को काट देना चाहिए। इन्हें 'रिनिवल स्पर' कहते हैं। आमतौर पर जिन शाखाओं पर फल लग चुके हों उन्हें ही रिनिवल स्पर के रूप में रखते हैं।

छंटाई करते समय रोगयुक्त एवं मुरझाई हुई शाखाओं को हटा दें एवं बेलों पर ब्लाईटोक्स ०.२ % का छिडकाव अवश्य करें।

किस्म कितनी आँखें छोडें

(१) ब्यूटी सीडलेस ३ - ३ (२) परलेट ३-४ (३) पूसा उर्वसी ३-५ (४) पूसा नवरंग ३-५ (५) पूसा सीडलेस ८-१०

सिंचाई - नवम्बर से दिसम्बर माह तक सिंचाई की खास आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बेल सुसुप्ता अवस्था में होती है लेकिन छंटाई के बाद सिंचाई आवश्यक होती है। फूल आने तथा पूरा फल बनने (मार्च से मई) तक पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस दौरान पानी की कमी से उत्पादन एवं हुन्वात्ता दोनों पर बुरा असर पडता है। इस दौरान तापमान तथा पर्यावरण स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ७ - १० दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फल पकने की प्रक्रिया शुरू होते ही पानी बंद कर देना चाहिए नहीं तो फल फट एवं सड सकते हैं। फलों की तुडाई के बाद भी एक सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए।

खाद एवं उर्वरक - अंगूर की बेल भूमि से काफी मात्र में पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। अतः मिट्टी कि उर्वरता बनाये रखने के लिए एवं लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए यह आवश्यक है की खाद और उर्वरकों द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति की जाये। पण्डाल पद्धति से साधी गई एवं ३ ट ३ मी. की दुरी पर लगाई गयी अंगूर की ५ वर्ष की बेल में लगभग ५०० ग्राम नाइट्रोजन, ७०० ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, ७०० ग्राम पोटेशियम सल्फेट एवं ५० - ६० कि.ग्रा. गोबर की खाद की आवश्यकता होती है।

खाद कब दें - छंटाई के तुंरत बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में नाइट्रोजन एवं पोटाश की आधी मात्र एवं फास्फोरस की सारी मात्र दाल देनी चाहिए। शेष मात्र फल लगने के बाद दें। खाद एवं उर्वरकों को अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद तुंरत सिंचाई करें। खाद को मुख्य तने से दूर १५-२० सेमी गहराई पर डालें।

कैसे करें फल गुणवत्ता में सुधार - अच्छी किस्म के खाने वाले अंगूर के गुच्छे मध्यम आकर, मध्यम से बडे आकर के बीजरहित दाने, विशिष्ट रंग, खुशबू, स्वाद व बनावट वाले होने चाहिए। ये विशेषताएं सामान्यतः किस्म विशेष पर निर्भर करती हैं। परन्तु निम्नलिखित विधियों द्वारा भी अंगूर की गुणवत्ता में अपेक्षा से अधिक सुधार किया जा सकता है।

फसल निर्धारण - फसल निर्धारण के छंटाई सर्वाधिक सस्ता एवं सरल साधन है। अधिक फल, गुणवत्ता एवं पकने की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव छोडते हैं। अतः बेहतर हो यदि बाबर पद्धति साधित बेलों पर ६० - ७० एवं हैड पद्धति पर साधित बेलों पर १२ - १५ गुच्छे छोडे जाएं। अतः फल लगने के तुंरत बाद संख्या से अधिक गुच्छों को निकाल दें।

छल्ला विधि - इस तकनीक में बेल के किसी भाग, शाखा, लता, उपशाखा या तना से ०.५ से.मी. चौडाई की छाल छल्ले के रूप में उतार ली जाती है। छाल कब उतारी जाये यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। अधिक फल लेने के लिए फूल खिलने के एक सप्ताह पूर्व, फल के आकर में सुधार लाने के लिए फल लगने के तुंरत बाद और बेहतर आकर्षक रंग के लिए फल पकना शुरू होने के समय छाल उतारनी चाहिए। आमतौर पर छाल मुख्य तने पर ०.५ से.मी चौडी फल लगते ही तुंरत उतारनी चाहिए।

वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग - बीज रहित किस्मों में जिब्बरेलिक एसिड का प्रयोग करने से दानो का आकर दो गुना होता है। पूसा सीडलेस किस्म में पुरे फूल आने पर ४५ पी.पी.एम. ४५० मि.ग्रा. प्रति १० ली. पानी में, ब्यूटी सीडलेस मने आधा फूल खिलने पर ४५ पी.पी.एम. एवं परलेट किस्म में भी आधे फूल खिलने पर ३० पी.पी.एम का प्रयोग करना चाहिए। जिब्बरेलिक एसिड के घोल का या तो छिडकाव किया जाता है या फिर गुच्छों को आधे मिनट तक इस घोल में डुबाया जाता है। यदि गुच्छों को ५०० पी.पी.एम ५ मिली. प्रति १० लीटर पानी में इथेफोन में डुबाया जाये तो फलों में अम्लता की कमी आती है। फल जल्दी पकते हैं एवं रंगीन किस्मों में दानों पर रंग में सुधार आता है। यदि जनवरी के प्रारंभ में डोरमैक्स ३ का छिडकाव कर दिया जाये तो अंगूर १ - २ सप्ताह जल्दी पक सकते हैं।

फल तुडाई एवं उत्पादन - अंगूर तोडने के पश्चात् पकते नहीं हैं, अतः जब खाने योग्य हो जाये अथवा बाजार में बेचना हो तो उसी समय तोडना चाहिए। शर्करा में वृद्धि एवं तथा अम्लता में कमी होना फल पकने के लक्षण हैं। फलों की तुडाई प्रातः काल या सायंकाल में करनी चाहिए। उचित कीमत लेने के लिए गुच्छों का वर्गीकरण करें। पैकिंग के पूर्व गुच्छों से टूटे एवं गले सडे दानों को निकाल दें। अंगूर के अच्छे रख - रखाव वाले बाग से तीन वर्ष पश्चात् फल मिलना शुरू हो जाते हैं और २ - ३ दशक तक फल प्राप्त किये जा सकते हैं। परलेट किस्म के १४ - १५ साल के बगीचे से ३० - ३५ टन एवं पूसा सीडलेस से १५ - २० टन प्रति हैक्टेयर फल लिया जा सकता है।

बीमारियाँ एवं कीट - बीमारियाँ - उत्तरी भारत में अंगूर को मुख्यतः एन्थ्रक्नोज एवं सफेद चुरनी रोग ही मुख्य बीमारियाँ हैं। एन्थ्रक्नोज बहुत ही विनाशकारी रोग है। इसका प्रभाव फल एवं पत्ती दोनों पर होता है। पत्तों की शिराओं के बीच जगह - जगह टेढे-मेढे गहरे भूरे दाग पद जाते हैं। इनके किनारे गहरे भूरे या लाल रंग के होते हैं। परन्तु मध्य भाग धंसा हुआ हलके रंग का होता है और बाद में पत्ता गिर जाता है। आरम्भ में फलों पर धब्बे हल्के रंग के होते हैं परन्तु बाद में बडा आकर लेकर बीच में गहरे हो जाते हैं तथा चारों ओर से लालिमा से घिर जाते हैं। इस बीमारी के नियंत्रण हेतु छंटाई के बाद प्रभावित भागों को नष्ट कर दे। कॉपर आक्सीक्लोराइड ०.२% के घोल का छिडकाव करें एवम पत्ते निकलने पर ०.२ % बाविस्टिन का छिडकाव करें। वर्षा ऋतु में कार्बेन्डाजिम ०.२% का छिडकाव १५ दिन के अंतराल पर आवश्यक है।

सफेद चूर्णी रोग - अन्य फफूंद बीमारियों की अपेक्षा यह शुष्क जलवायु में अधिक फैलाती है। प्रायः पत्तों, शाखाओं, एवं फलों पर सफेद चूर्णी दाग देखे जा सकते हैं। ये दाग धीरे - धीरे पुरे पत्तों एवं फलों पर फैल जाते हैं। जिसके कारण फल गिर सकते हैं या देर से पकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए ०.२% घुलनशील गंधक, या ०.१% कैरोथेन के दो छिडकाव १० - १५ दिन के अंतराल पर करें।

कीट - थ्रिप्स, चैफर, बीटल एवं चिडिया, पक्षी अंगूर को हानि पहुंचाते हैं। थ्रिप्स का प्रकोप मार्च से अक्तूबर तक रहता है। ये पत्तियों, शाखाओं, एवं फलों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ५०० मिली. मेलाथियान का ५०० लीटर पानी में घोल बनाकर छिडकाव करें।

चैफर बीटल कीट रात में पत्तों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करता है, वर्षाकाल में १० दिन के अंतराल पर १० % बी.एच.सी. पावडर बुरक देना इस कीट के नियंत्रण हेतु लाभदायक पाया गया है।

चिडिया अंगूर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। फल पकने के समय चिडिया गुच्छे खा जाती है। अतः घर से आंगन में लगी बेल के गुच्छों को हरे रंग की मलमल की थैलियों से ढक देना चाहिए। बडे - बडे बगीचों में नाइलोन के जाल से ढक दें , ढोल बजाकर चिडियों से छुटकारा पाया जा सकता है।

प्याज की खेती के लिए नये हल की ईजाद

शेखपुरा : प्याज की खेती के लिए मजदूरों की कमी से जूझ रहे किसानों को जल्द ही राहत मिल जायेगी. एकसारी गांव निवासी शशिभूषण ने एक ऐसे हल की ईजाद की है, जो प्याज की खेती के लिए १यारी बनाने में किसानों को राहत पहुंचा रहा है.

लंबी अवधि और ज्यादा मजदूरी भुगतान कर १यारी बनवाने को विवश किसान इस नये हल का लाभ उठा कर सस्ते दर पर कम समय में १यारी तैयार कर सकते हैं.

घंटों का काम मिनटों में

किसानों की मानें, तो प्याज फसल बोने के लिए किसानों को एक एकड खेत में १यारी बनाने में चार मजदूरों को पांच दिन का समय लगता था. एक एकड १यारी बनाने में लगभग तीन से चार हजार की लागत आती है, परंतु ट्रैक्टर से संचालित इस नये हल से मात्र दो घंटे में एक एकड १यारी का निर्माण कर लिया जाता है.

प्याज की खेती के लिए गढ माने जानेवाले शेखपुरा में शशिभूषण के इस खोज को किसान बडी उपलब्धि मान रहे हैं. शशिभूषण बताते हैं कि ट्रैक्टर हल से संचालित कल्टी हल से प्रेरणा लेकर निर्माण किया है.

ट्रैक्टर से संचालित इस नये हल का उपयोग प्याज के साथ-साथ आलू की खेती के लिए भी कारगर साबित होगा. शशिभूषण ने बताया कि इस हल के निर्माण में पुराने हल में सेटिंग करने के लिए मात्र दो हजार रुपये की लागत लगती है.

बढ रही मांग

प्याज की खेती के लिए मजदूरों की जटिल समस्या से परेशान शशिभूषण ने वैकल्पिक रास्ते के लिए संकल्प लिया. काफी मंथन के बाद एक नक्शे को तैयार कर नतीजे पर पहुंचे. तोड-जोड के बाद सोमवार के दिन शशि की मेहनत रंग लायी. शशि के पास जरतमंद कृषकों के काफी फोन आ रहे हैं.

मिलेंगे डीएम से

क्यारी निर्माण के लिए नयी खोज करनेवाले शशिभूषण अपने द्वारा बनाये गये हल को लेकर जिलाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव से मिल कर इससे अवगत करायेंगे. नये खोज के विस्तार के साथ इस पर अनुदान का भी प्रस्ताव रखेंगे.

कानपुर में 'जीरो बजट' खेती

(पान १ से) कानपुर और उसके आसपास के करीब १०० एकड क्षेत्र में यह खेती की जा रही है। इस जीरो बजट खेती के जनक महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर है जिनसे कानपुर के कुछ किसानों ने इस खेती के गुण सीखें और अब इसे यहां अपना रहे है।

जिलाधिकारी मुकेश मेश्राम कानपुर के कुछ किसानों के इस जीरो बजट खेती के प्रयासों से इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने कानपुर मंडल के करीब १५०० किसानों को इस नई तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए आगामी २१ से २४ अक्टूबर तक एक शिविर का आयोजन किया है। सम्मेलन में इस खेती के जनक महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर को बुलाया गया है ताकि वह अपने अनुभव बाकी के किसानों के साथ बांट सकें। चार दिन के प्रशिक्षण शिविर में आने वाले सभी किसानों के खाने-पीने तथा रहने का पूरा प्रबंध प्रशासन करेगा।

कानपुर और उन्नाव जिलों में कई एकड क्षेत्र में जीरो बजट खेती करने वाले एक किसान विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि हम इस खेती में न तो रासायनिक खाद और न ही बाजार में बिकने वाले कीटनाशकों या फिर हाईब्रिड बीजों का इस्तेमाल करते हैं।

उन्होंने बताया रासायनिक खाद के स्थान पर वह खुद की तैयार की हुई देशी खाद बनाते हैं जिसका नाम ३घन जीवा अमृत रखा है। यह खाद गाय के गोबर, गौमूत्र, चने के बेसन, गुड, मिटटी तथा पानी से बनती है।

उन्होंने कहा वह रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर नीम, गोबर और गौमूत्र से बना ३नीमास्त्र इस्तेमाल करते हैं। इससे फसल को कीडा नहीं लगता है। संकर प्रजाति के बीजों के स्थान पर देशी बीज डालते हैं। चतुर्वेदी कहते हैं कि देशी बीज चूँकि हमारे खेतों की पुरानी फसल के ही होते हैं इसलिए हमें उसके लिए पैसे नहीं खर्च करने पडते हैं जबकि हाईब्रिड बीज हमें बाजार से खरीदने पडते हैं जो काफी महँगे होते हैं।

जीरो बजट खेती में खेतों की सिंचाई, मडाई और जुताई का सारा काम बैलो की मदद से किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के डीजल या ईधन से चलने वाले संसाधनों का प्रयोग नहीं होता है जिससे काफी बचत होती है।

जिलाधिकारी मेश्राम ने बताया कि जब प्रशासन को इस 'जीरो बजट खेती' के बारे में पता चला तो कानपुर के कुछ किसानों को इसका प्रशिक्षण लेने के लिए महाराष्ट्र में सुभाष पालेकर के पास भेजा गया। परिणाम उत्साह जनक रहे। किसानों ने करके दिखाया कि कैसे बहुत कम खर्च यानी जीरो बजट में अपने ही खेतों से अधिक फसल उगाई जा सकती है।

उन्होंने बताया कि जब से इस खेती के बारे में प्रचार-प्रसार हुआ है तब से दूसरे प्रदेशों के किसान भी इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और वह भी इस खेती के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें छत्तीसगढ, बिहार, मध्यप्रदेश के किसान प्रमुख है।

जिलाधिकारी ने बताया कि अगले महीने बांदा जिले में अखिल भारतीय प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है जिसमें पूरे देश के किसान शामिल होंगे और विदेशों से आने वाले किसानों को भी इसमें आने की अनुमति दी जाएँगी। वह कहते हैं कि जीरो बजट खेती अभी तो एक शुरुआत है धीरे-धीरे यह पूरे देश में एक क्रांति के रूप में फैल जाएँगी।

दिल्ली में मोदी की दावेदारी

(पान १ से) जिस तरह की राजनीतिक अनिश्चितता है उसमें कोई और नाम भी सामने आ जाए तो आश्चर्य नहीं। कांग्रेस विकल्पहीन है, इसलिए राहुल गांधी का नाम सबसे आगे हैं। भाजपा में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होने के कारण नरेंद्र मोदी की दावेदारी बढ रही है, लेकिन शेष तीन संभावित दावेदार इस आकलन पर अटके हैं कि २०१४ के निर्वाचन में कांग्रेस और भाजपा सौ-डेढ सौ सीटों तक सिमट जाए। ऐसे में मुलायम, मायावती और नीतीश तीनों को कांग्रेस से समर्थन की आस है। वे मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस के पास भाजपा को रोकने का एक ही विकल्प रह जाएगा- किसी गैर संप्रग दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाना। तीनों इसी रणनीति के मद्देनजर फिलहाल प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर रहे हैं। मायावती और मुलायम सिंह तो बिना मांगे २००९ से समर्थन देते आ रहे हैं।

नीतीश कुमार अब मैदान में आए हैं। गैर कांग्रेस और गैर भाजपा दलों की स्थिति चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन कोई भी क्षेत्रीय दल किसी अन्य क्षेत्रीय दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाना पसंद नहीं करेगा। राजनीतिक असंतुष्टवाद की प्रतीक बन चुकीं ममता बनर्जी १या करेंगी इस पर सभी की निगाहें हैं। वह मुलायम सिंह के घात से बहुत आहत हैं और न चाहते हुए भी संप्रग में बनी हुई हैं। संभव है राष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी मतदान में भाग ही न लें। जनता कांग्रेस के विकल्प के लिए व्याकुल है। कांग्रेस का अंतर्विरोध मुखरित नहीं है, लेकिन भाजपा में अंतर्विरोध सिर चढकर बोल रहा है। मनमोहन सरकार सबसे भ्रष्ट और निकम्मी है यह अब जनता जान चुकी है। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह कोई भी छाप छोडने में असफल रहे हैं। तमाम कांग्रेसियों को संदेह है कि २०१४ में उनकी पार्टी की लोकसभा सदस्यों की संख्या तीन अंकों में पहुंच भी सकेगी या नहीं? अन्य आकलन भी कांग्रेस की वापसी की धारणा को धूमिल कर रहे हैं। साथ ही उसे इस बात की भी चिंता है कि विकल्प के रूप में खडी भाजपा क्या दो सौ के आसपास सीटें जीत सकेगी? कांग्रेस शासित राज्यों की तुलना में भाजपा की कहीं अधिक राज्यों में सरकार है। उसके अधिकांश मुख्यमंत्री अपनी कार्यक्षमता और बेदाग राजनीतिक जीवन के लिए चर्चित हैं, लेकिन देश की सर्वोपरि सत्ता जिस भावना के कारण प्राप्त हुई थी आज वह शीर्षस्थ लोगों में परस्पर टकराव के कारण नदारद है। अभी चुनाव में दो वर्ष बाकी हैं। यदि कांग्रेस दागियों को दंडित करने और अर्थव्यवस्था सुधारने में सफलता प्राप्त करती है तो उसकी वर्तमान सदस्य संख्या ज्यादा कम नहीं होगी। इसी तरह यदि भाजपा नेता वे चाहे दिल्ली में बैठे हों या राज्यों में, अपने व्यक्तिगत अहंकार और निजी स्वार्थ से ऊपर उठते हैं और एकजुट होकर जनता के सामने आते हैं तो उनके लिए खुद के बल पर सरकार बनाना संभव हो सकता है।

कांग्रेस के लिए फिलहाल वर्तमान दौर से निकल पाना मुश्किल है, लेकिन भाजपा के लिए अहंकार से स्वाभिमान की ओर लौटना संभव है। यदि आचरण में बडों के प्रति सम्मान और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दलीय हित में त्यागकर एकरूपता का पुराना विराट स्वरूप दिखे तो ही भाजपा के लिए कोई संभावना बन सकती है। एक बात यह भी कि कांग्रेस अथवा भाजपा को कोई ऐसा नेता आगे करना पडेगा, जिसे अन्य दलों का भी समर्थन हासिल हो सके।कांग्रेस के पास ऐसा एक ही व्यक्ति था जिसे उसने राष्ट्रपति भवन की ओर भेज दिया है, लेकिन भाजपा के पास ऐसे कई नेता हैं जिनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या फिर जसवंत सिंह का नाम लिया जा सकता है।

घर बैठे मिलेंगे आधुनिक खेती के गुर

(पान १ से) इसमें सर्दी की मौसम में बगीचों की देखभाल, पुष्प उत्पादन, सब्जियों व जडी-बूटियों के उत्पादन व प्रूनिंग, नई दवाइयों सहित सभी नई तकनीकों की जानकारी दी गई। डा. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन के कृषि विज्ञानिक डा. जीके शर्मा ने बताया कि प्रदेशभर में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि प्रदेश के किसान कृषि की नई तकनीकों से अवगत हों।

प्यासे भारत की दरियादिली

पारस्परिक आदान-प्रदान कूटनीति का पहला सिद्धांत है, किंतु भारत के लिए नहीं। पडोसियों से दोस्ती की खातिर भारत हदें लांघता रहा है, फिर भी आज वह समस्या खडी करने वाले पडोसियों से घिरा हुआ है। भूमि के मुद्दे पर भारत की उदारता की काफी चर्चा हुई है। भारत १९५४ में तिब्बत पर ब्रिटिश वंशागत अपरदेशीय अधिकार को तिलांजलि दे चुका है, १९६५ के युद्ध के बाद पाकिस्तान को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हाजी पीर वापस कर चुका है और १९७१ के युद्ध के बाद भूभाग लाभ तथा ९३००० सैनिकों को वापस लौटाने की उदारता दिखा चुका है। ये सब त्याग बिना पारस्परिक आदान-प्रदान के हुए हैं। इस रेकॉर्ड के बावजूद, आज भारत के अंदर से ही सियाचिन ग्लेशियर से नियंत्रण हटाने की मांग की जा रही है। बहुत कम लोगों को यह पता है कि पडोसियों के प्रति जल संकट से जूझ रहे भारत की उदारता भूभाग लौटाने तक ही नहीं, बल्कि नदियों का पानी लुटाने तक विस्तारित है। जल बंटावारे के विश्व के सर्वाधिक उदार समझौते का श्रेय भारत को जाता है। १९६० में भारत ने छह नदियों का ८०.५२ फीसदी पानी पाकिस्तान के लिए छोड दिया और खुद अपने लिए महज १९.४८ फीसदी पानी ही रखा। पडोसी राष्ट्र के लिए छोडे जाने वाले पानी की कुल मात्रा तथा अनुपात दोनों ही दृष्टि से अब तक कोई भी अंतरराष्ट्रीय जल संधि इस समझौते की बराबरी नहीं कर पाई है। वास्तव में, अमेरिका जितना पानी मेक्सिको के लिए छोडता है, भारत उसका ९० गुना पानी पाकिस्तान के लिए छोड रहा है। भारत इस संधि से अनिश्चित काल तक के लिए बंधा हुआ है। महत्वपूर्ण यह है कि भारत बांग्लादेश के साथ भी इसी तरह के जाल में न फंस जाए।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस में आईसीएआर ने पब्लिक आउटरीच सत्र का आयोजन किया

कोलकाता- भारतीय विज्ञान कांग्रेस के १००वें सत्र के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कोलकाता के राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान में पब्लिक आउटरीच सत्र का आयोजन किया। डॉ. एस. अय्यप्पन, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, आईसीएआर ने सत्र की अध्यक्षता की तथा छात्रों, युवा शोधार्थियों, किसानों, विस्तार कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों से वार्तालाप किया। अपने सम्बोधन में डॉ. अय्यप्पन ने कृषि और कृषिगत अनुसंधान में पर्याप्त रोजगार अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में आधुनिक कृषिगत तकनीकों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। डॉ. अय्यप्पन ने कहा कि हमें कृषि अनुसंधान और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों से जुडे होने पर गर्व करना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र को खाद्य सुरक्षा दे रहे हैं। उन्होंने छात्रों से अन्य आकर्षक क्षेत्रों की तरह ही कृषि अनुसंधान को आकर्षक रोजगार के रूप में चुनने का आह्वान किया।

इससे पूर्व, डॉ. रामेश्वर सिंह, परियोजना निदेशक, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय ने आईसीएआर के विकास की यात्रा और सफलताओं पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कृषि शिक्षा, भर्ती प्रक्रिया तथा छात्रवृत्ति और फैलोशिप पुरस्कारों के बारे में भी बताया। डॉ. ए.के. सिंह, क्षेत्रीय परियोजना निदेशक, जोन-", कोलकाता ने युवा शोधार्थियों और छात्रों से कृषि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर आम लोगों के लाभ के लिए अर्थपूर्ण शोध करने का आह्वान किया। डॉ. जगदीप सक्सेना, सम्पादक, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय ने कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा देश भर में आईसीएआर के अनुसंधान एवं संस्थागत नेटवर्क पर प्रकाश डाला।

एनडीआरआई, करनाल; सीफा, भुवनेश्वर; एबीएफजीआर, लखनऊ; पशु निदेशालय, मेरठ; यूबीकेवी, कूचबिहार; डब्ल्यूबीयूएएफएस, कोलकाता; बीएयू, साबौर के शिक्षा विस्तार निदेशक; निदेशक, समेती, पश्चिम बंगाल तथा स्थानीय आईसीएआर संस्थानों के विशेषज्ञों ने लोगों से वार्तालाप किया तथा कृषि शिक्षा, रोजगार, विस्तार तथा विभिन्न कृषि प्रणालियों से सम्बन्धित लोगों के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा में दिए।

इस आउटरीच सत्र में युवा शोधार्थियों, विस्तार कार्यकर्ताओं, किसानों तथा आमलोगों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को आईसीएआर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण साहित्य तथा परिषद के क्रियाकलापों और सफलताओं पर प्रकाश डालने वाली फिल्म ड्राईवर्स ऑफ चेंज का भी प्रदर्शन किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय (डीकेएमए) तथा क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, जोन-", कोलकाता द्वारा किया गया।

डॉ. एफ.एच. रहमान, वरिष्ठ वैज्ञानिक, क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, जोन-" ने कार्यक्रम का संयोजन किया।

एक और कूटनीतिक विफलता

भारत १९९६ में बांग्लादेश के साथ संधि कर चुका है, जिसके तहत फरक्का से लगभग आधा पानी अपने इस पडोसी के लिए छोडा जा रहा है। अब शेख हसीना के हाथ मजबूत करने के लिए भारत तीस्ता नदी का आधा पानी बांग्लादेश के लिए छोडने को तैयार नजर आ रहा है। शेख हसीना भारत की मित्र हो सकती हैं, किंतु वह हमेशा के लिए बांग्लादेश की शासक नहीं रहेंगी और भविष्य में वहां भारत विरोधी शक्तियां सत्ता में आ सकती हैं। जल कूटनीति में भारत की शिकस्त इस बात से सिद्ध हो जाती है कि चीन से बहकर भारत आने वाली नदियों के संबंध में बीजिंग दिल्ली को ८० फीसदी जल देना तो दूर, जल समझौते की अवधारणा तक से इन्कार कर रहा है। विपुल जलधाराओं से लैस चीन एशिया के जल संसाधनों पर पकड मजबूत रखने की मंशा से भारतीय हितों को चुनौती दे रहा है। वैसे तो अफगानिस्तान से लेकर वियेतनाम तक अनेक देश तिब्बत से निकलने वाली नदियों का जल प्राप्त करते हैं, किंतु भारत की तिब्बती पानी पर निर्भरता इन सभी देशों से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के हालिया आंकडों के अनुसार तिब्बती हिमालयी क्षेत्र से बहने वाली करीब एक दर्जन नदियों से भारत को अपनी आपूर्ति का एक-तिहाई जल मिलता है। यानी साल में करीब १,९११ क्यूबिक किलोमीटर जल भारत को मिलता है। तिब्बत से बहकर भारत आने वाली तमाम नदियों में ब्रह्मपुत्र सबसे बडी है। भारत में आने से पहले यह नदी हिमालय के ग्लेशियरों से होती हुई पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। बर्फ और पिघले हुए ग्लेशियर का पानी इस नदी को इतना विशाल बनाता है।

भारत में प्रवेश के समय ब्रह्मपुत्र का सीमा पार जल प्रवाह एशिया में सबसे अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की दक्षिण सीमा के करीब से हिमालयी ढलानों पर करीब २२०० किलोमीटर बहते हुए हिमालय की बेहद उर्वर गाद अपने साथ लाती है। ब्रह्मपुत्र के पानी में घुली-मिली इस पोषक गाद के कारण ही असम के मैदानी इलाकों और बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से की जमीन फिर से उर्वरा शक्ति से भर जाती है। हर साल ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ से ये पोषक तत्व पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के मैदानों में दूर-दूर तक समा जाते हैं और इस प्राकृतिक तालाब की अवस्था में किसान धान की भरपूर पैदावार लेते हैं। इसके अलावा वहां मछली पालन भी बडे पैमाने पर किया जाता है। ब्रह्मपुत्र की निचली खाडी की उर्वर भूमि गाद की इस सालाना भेंट पर निर्भर करती है। यही नहीं बंगाल की खाडी में समुद्री जीवन भी ब्रह्मपुत्र और अन्य हिमालयी नदियों से पोषक तत्व हासिल करता है। चीन में ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने के कारण भारत और बांग्लादेश के किसान प्रकृति के इस अनमोल उपहार से वंचित रह जाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की अधिकांश पोषक गाद प्राकृतिक रूप से बहकर भारत और बांग्लादेश आने के बजाय बांधों में रुक जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे थ्री जॉर्जेस बांध यांग्जे नदी की गाद को थाम लेता है और यह जलकुंडों में जमा हो जाती है।

चीन में ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से सूखे मौसम में भारत में आने वाले पानी की मात्रा कम हो जाएगी। इसके अलावा चीन को अपनी मर्जी से भारत में पानी छोडने या रोकने का औजार भी मिल जाएगा। एक प्रभावशाली चीनी शिक्षाविद ने मुझे बताया था कि तिब्बती नदियों का रुख मोडने का फैसला लेते समय चीनी नीतिनिर्माताओं के सामने दो ही विकल्प हैं। एक तो चीन की उत्तरी आबादी की प्यास बुझाना तथा दूसरा भारत तथा अन्य देशों को नाराज न करना। और इन विकल्पों में से चुनाव कोई मुश्किल नहीं है। सीधा-सा तथ्य यह है कि जब राष्ट्रीय हितों का सवाल आता है तो चीन अन्य देशों के असंतोष और नाराजगी की जरा भी परवाह नहीं करता। इसकी नीतियां राष्ट्रीय हित साधने के लिए बनी हैं न कि दूसरे देशों का अनुमोदन हासिल करने या फिर उनकी नाराजगी दूर करने के लिए। भारत को भी अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे में यह पूछना उचित है कि क्या अपने पडोसियों के प्रति शाश्वत उदारता के लिए भारत की भर्त्सना की जानी चाहिए? इस सवाल का जवाब जल्द चाहिए क्योंकि भारत ने अपनी नई सहायता नीति पर चलना शुरू कर दिया है-एक अरब डॉलर बांग्लादेश को, पचास करोड डॉलर म्यांमार को, ३० करोड डॉलर श्रीलंका को, १४ करोड डॉलर मालदीव्ज को। इसके अलावा अब अफगानिस्तान और नेपाल को भी उदार सहायता दी जा रही है। इस सहायता उदारता का नतीजा भी जल और भूमि उदारता के समान होगा। कूटनीति में उदारता का लाभांश तभी मिल सकता है, जब इसके माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा कि स्थिति में सुधार आता हो ताकि भारत व्यापक वैश्विक भूमिका निभा सके। किंतु अगर यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मूल तत्व नहीं है, तो भारत अपने भूभाग पर अत्याचार कर रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटींग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगाव, पूर्व, मुंबई- 62 से मुद्रीत किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड, मालाड, पश्चिम, मुंबई- 400064 यहाँ से प्रकाशित किया। संपादक- सुरेश जी. शर्मा। सत्यापित शीर्षक कन्मांक- MAH/HIN/50786 /13/1/2013 T.C.